दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२०५ वा | बुधवार २६ फ़रवरी २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

साल में दो बार होंगी सीबीएसई बोर्ड १० वीं की परीक्षा

दिल्ली। संवादाता

२०२६ से सीबीएसई बोर्ड १०वीं की परीक्षा साल में दो बार आयोजित होंगी। शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) २०२० के तहत चल रहे सुधारों के क्रम में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक अहम मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी है। दरअसल, शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में बोर्ड के उस ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई जिसमें १०वीं बोर्ड की परीक्षा साल में दो बार आयोजित कराने की बात रखी गई थी।

बोर्ड ने सीबीएसई १०वीं बोर्ड परीक्षा २०२६ को साल में दो बार आयोजित करने का प्रस्ताव जारी किया। शिक्षा मंत्रालय ने माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी की जहां इस नीति परिवर्तन पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्ताव का उद्देश्य छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का मौका देना है, जिससे छात्रों पर दबाव और तनाव कम हो। शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। अब २०२६ से १०वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार होंगी। बोर्ड के इस ड्राफ्ट के अनुसार, २०२६ से १०वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित होंगी। बोर्ड एग्जाम का पहला फेज फरवरी□मार्च में और दूसरा फेज मई में निर्धारित रहेगा। दोनों परीक्षाओं में पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा, जिससे छात्रों के ज्ञान और कौशल का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित होगा। दोनों फेज की परीक्षाओं का रिजल्ट भी अलग□अलग जारी होगा। इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा।

मध्यरात्री जयंत पाटील और बावनकुळे की गुप्त मुलाकात: महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल

मुंबई:(संवाददाता)राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे की मध्यरात्री गुप्त बैठक ने महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं को जन्म दिया है। यह बैठक मुंबई स्थित बावनकुळे के निवास पर हुई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक चर्चा चली।

जयंत पाटील का स्पष्टीकरण

इस मुलाकात पर सफाई देते हुए जयंत पाटील ने कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े राजस्व विभाग के मुद्दों को लेकर बावनकुळे से मुलाकात की थी और उन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञापन सौंपे थे। वहीं, बावनकुळे ने भी इसे एक व्यक्तिगत मुलाकात बताया है।

राजनीतिक अटकलें तेज हालांकि, इस बैठक के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। जयंत पाटील ने अभी तक राज्य की महत्वपूर्ण घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं। इस मामले पर अजित पवार गुट के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शरद पवार गुट में अंदरूनी कलह के कारण जयंत पाटील असंतुष्ट हैं, और अगर वे कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। सत्ता समीकरणों पर प्रभाव संभव इस घटनाक्रम का असर राज्य के सत्ता संतुलन पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में इस मुलाकात के राजनीतिक नतीजे कैसे सामने आते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

ना. पंकजा मुंडे का परलीवासियों को नए साल का पहला तोहफा

पशुचिकित्सा महाविद्यालय को कैबिनेट की मंजूरी, ५६४.५८ करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति

मुंबई, २५ फरवरी: (संवाददाता)

महाराष्ट्र की पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और पशुसंवर्धन मंत्री ना. पंकजा मुंडे ने परली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को महाशिवरात्रि और नए साल का पहला तोहफा दिया है। परली में एक नया पशुचिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए ५६४.५८ करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है।

परली में पशुचिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी

ना. पंकजा मुंडे के पशुसंवर्धन मंत्री बनने के बाद, उन्होंने परली में पशुचिकित्सा महाविद्यालय की मंजूरी दिलाकर विकास केंद्रित कार्यों की शुरुआत की। उनके निर्देशानुसार, महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर की एक टीम ने ९ फरवरी को परली शहर के मेरु पर्वत और लोणी में जमीन का निरीक्षण किया था। टीम ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया कि इन दोनों स्थानों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, जल आपूर्ति और अन्य संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे महाविद्यालय की स्थापना में कोई अड़चन नहीं आएगी।

कैबिनेट की मंजूरी और बजट आवंटन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में और उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परली में पशुचिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए ५६४.५८ करोड़ रुपये की बजट स्वीकृति दी गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए ना. पंकजा मुंडे ने मुख्यमंत्री फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्रियों का आभार व्यक्त किया। परली के विकास को नई दिशा

इस फैसले से परली और आसपास के क्षेत्रों में पशुपालन और कृषि से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। पशुचिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से शिक्षा, अनुसंधान और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। इस फैसले को परली के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

चार कुख्यात बदमाश एक साथ जिला बदर

बीड जिले में आतंक फैलाने वालों पर एसपी की सख्त कार्रवाई

बीड, २५ फरवरी (प्रतिनिधि):

बीड जिले में अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के बाद, पुलिस अधीक्षक (एसपी) नवनीत कॉवत ने अब जिले में आतंक फैलाने वाले चार कुख्यात बदमाशों को जिला बदर करने का फैसला लिया है। ये चारों अपराधी अगले दो वर्षों तक जिले से बाहर रहेंगे।

गंभीर अपराधों में शामिल थे बदमाश

बीड जिले में चोरी, डकैती, हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट और दहशत फैलाने वाले गिरोहों पर पुलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत ने कड़ी नजर रखी। अपराधी प्रवृत्ति के ऐसे तत्वों पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा ५५ के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें जिला बदर करने का निर्णय लिया गया।

जिला बदर किए गए अपराधियों के नाम:

अजय अशोक तांदळे (२३ वर्ष, निवासी कोरेगांव, तहसील केज), विकास सुभाष सावंत (२८ वर्ष, निवासी सावंतवाड़ी, तहसील केज), सोमनाथ राजाभाऊ चाळक (२२ वर्ष, निवासी लव्हरी, तहसील केज), बालाजी राम लांब (१९ वर्ष, निवासी कोरेगांव, तहसील केज), इन अपराधियों पर गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखना, जबरन वसूली, लूटपाट और लोगों में दहशत पैदा करना शामिल है। इनकी वजह से स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ था।

दिदार सेठ बागवान का इंतेकाल

बीड (संवाददाता)

बीड के प्रसिद्ध व्यापारी हाजी दिदार बशीरदोन

सेठ बागबान का २५ फरवरी को इंतेकाल हो गया उनकी नमाज़ ए जनाजा व तदफीन तकिया मस्जिद ऐहाते में रात आठ बजे अमल में आई, मरहुम नेक और नमाज रोजे के पाबंद थे व भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन कि उम्र साठ साल थी, अल्लाह से दुआ है कि वो मरहूम को जनततूल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और फमेली को सब्र जमील अता करे दैनिक तामीर बागवान फमेली के ग़म में बराबर का शरीक हैं।

‘सारथी’ के ड्रोन पायलट प्रशिक्षण से रोजगार के अवसर

अगले पांच वर्षों में राज्य में दो लाख ड्रोन का उपयोग; नौकरी का नया विकल्प

बीड (संवाददाता)

राज्य में अगले पांच वर्षों में कृषि और अन्य क्षेत्रों में कम से कम दो लाख ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। इन ड्रोन को संचालित करने के लिए बड़ी संख्या में पायलटों की जरूरत होगी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'सारथी' संस्था ने मराठा समाज के युवाओं के लिए 'सेनापति धनाजी जाधव सारथी शेतकरी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम' शुरू किया है। यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाएगा।

२६० ड्रोन पायलट तैयार, ७०० उम्मीदवार प्रतीक्षारत

पिछले एक वर्ष में इस कार्यक्रम के तहत २६० ड्रोन पायलट प्रशिक्षित किए गए हैं, जिनमें से कई ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया है। फिलहाल ७०० उम्मीदवार अभी भी प्रशिक्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पहल को महिलाओं का भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

राज्य में मजदूरों की कमी के कारण कृषि संकट का सामना कर रही है। फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए खाद और कीटनाशकों का छिड़काव आवश्यक होता है, लेकिन मजदूरों की कमी इस प्रक्रिया में बाधा बन रही है। ऐसे में ड्रोन एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। इससे न केवल श्रमिकों की कमी दूर होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी।

ड्रोन का उपयोग केवल कृषि में ही नहीं, बल्कि उद्योग, रक्षा, भूमि सर्वेक्षण और अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इन्हें संचालित करने के लिए प्रशिक्षित पायलटों की जरूरत होती है। इसी को देखते हुए सारथी संस्था ने यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

दो श्रेणियों में मिलेगा प्रशिक्षण

यह प्रशिक्षण उन मराठा और कुनबी समाज के युवाओं के लिए है, जिनकी वार्षिक आय ८ लाख रुपये से कम है। इन उम्मीदवारों को नागरिक विमानन महानिदेशालय (ऊ्रूछ□) से मान्यता प्राप्त केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण दो चरणों में होगा □

७ दिन का प्रशिक्षण

१८० दिन का प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण का पूरा खर्च सारथी संस्था वहन कर रही है। यह प्रशिक्षण परभणी, राहुरी और दापोली कृषि विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण केंद्रों में दिया जाएगा। इसे जिला स्तर पर जिला परिषद की उमेद शाखा के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

ड्रोन खरीदने की चुनौती, सरकार को उठाने होंगे कदम

प्रशिक्षित पायलटों के लिए ड्रोन संचालन में व्यवसाय के कई अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। कई पायलट स्वरोजगार की राह पर भी बढ़ चुके हैं। लेकिन ड्रोन की ऊंची कीमत अब भी बड़ी समस्या बनी हुई है। इस कारण कई युवाओं के लिए अपना व्यवसाय शुरू करना मुश्किल हो रहा है। सरकार को ड्रोन खरीद को सुलभ और सस्ता बनाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है।

ड्रोन से फसल छिड़काव केवल ६ मिनट में संभव

बीड जिले के सौ. के.एस.के. (काकू) कृषि महाविद्यालय की छात्रा नूतन टेमगिरे ड्रोन पायलटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने बताया,

*वर्तमान में कृषि मजदूरों की भारी कमी है। मैंने सारथी संस्था से प्रशिक्षण लेने के बाद जून २०२४ से अपने खेतों में ड्रोन का उपयोग शुरू किया। जहां मजदूरों के माध्यम से एक एकड़ खेत में छिड़काव करने में पूरा दिन लग जाता था, वहीं ड्रोन से यह कार्य मात्र ६ मिनट में पूरा हो जाता है। इस व्यवसाय से मुझे हर महीने *६०,००० से ८०,००० रुपये तक की कमाई हो रही है।

निष्कर्षः ड्रोन पायलटिंग कृषि और अन्य क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन ड्रोन की ऊंची कीमत और सरकारी सहायता की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यदि सरकार इसमें सहयोग करे, तो यह एक सशक्त आजीविका विकल्प बन सकता है।

पुणे के किसान ने मंत्रालय में कूदकर आत्महत्या की कोशिश, पुलिस में मची अफरा-तफरी

मुंबई, (जमीर काजी)

मंत्रालय में आगंतुकों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, आंदोलन और आत्महत्या के प्रयासों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मंगलवार को पुणे के एक किसान ने मंत्रालय की सातवीं मंजिल से सुरक्षा जाली पर कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस घटना से कुछ देर के लिए मंत्रालय परिसर में अफरा□तफरी मच गई और पुलिस को तुरंत हरकत में आकर बचाव कार्य करना पड़ा।

कौन है आत्महत्या का प्रयास करने वाला किसान?

आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसान का नाम विजय परबती साष्टे (निवासी रामनगर, दत्तनगर, वारजे माळवाडी, पुणे) बताया गया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उन्होंने सातवीं मंजिल से दूसरी मंजिल की सुरक्षा जाली पर छलांग लगा दी।

८० फीट ऊंचाई से कूदने से हुआ गंभीर चोटिल

करीब ८० फीट ऊंचाई से कूदने के कारण उनके सीने और गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत जी.टी. अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

क्यों किया आत्महत्या का प्रयास?

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विजय साष्टे अपनी जमीन से जुड़े विवाद को लेकर परेशान थे। उनका आरोप है कि उनकी गायरान जमीन (सरकारी चरागाह भूमि) को किसी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हड़प लिया और प्रशासन द्वारा उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की

जा रही थी। क्या है पूरा मामला? विजय साष्टे के अनुसार, पुणे के वारजे गांव में स्थित गट नंबर ३३/१बी/१ (क्षेत्रफल ५४ गुंठे) की जमीन से सटी हुई तीन एकड़ गायरान भूमि को वन विभाग की जमीन बताकर हड़प लिया गया। यह जमीन कथित तौर पर पुणे महानगरपालिका के दगडू भिकोबा बराटे (निवासी वारजे) ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने नाम करवा ली। साष्टे का दावा है कि बराटे ने खुद को पुलिस पाटील (गांव का सरकारी अधिकारी) बताकर यह जमीन अपने नाम करवाई, जबकि वह पुलिस पाटील नहीं हैं। इस मामले की शिकायत राजस्व विभाग से की गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन की लापरवाही और न्याय न मिलने से हताश होकर विजय साष्टे ने आत्महत्या का प्रयास किया। मंत्रालय में मची अफरा□तफरी मंगलवार शाम करीब ४ बजे, साष्टे सातवीं मंजिल पर पहुंचे और अचानक दूसरी मंजिल की सुरक्षा जाली पर कूद गए।उस समय मंत्रालय में महिला उद्यमियों का एक प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा था, जहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। घटना होते ही वहां अफरा□तफरी मच गई। दो पुलिसकर्मी तुरंत जाली में कूदे और करीब २० मिनट की मशक्कत के बाद साष्टे को बाहर निकाला। उनकी हालत बिगड़ते देख तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई और उन्हें जी.टी. अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन की लापरवाही पर सवाल इस घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर समय रहते किसान की शिकायत पर कार्रवाई होती, तो आज उसे आत्महत्या का प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाएगा, यह देखने वाली बात होगी।

सीएसआर निधि के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों का विकास होगा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई,(जमीर काजी)

आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार पूरी मेहनत कर रही है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड के माध्यम से संतुलित विकास किया जाएगा। यह आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को दिया।

मुख्यमंत्री फडणवीस मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित आदिवासी विकास विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा अधिक बल फडणवीस ने कहा कि आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं

तेजी से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सीएसआर निधि केवल महानगरों में खर्च करने के बजाय संतुलित विकास के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, इस फंड का अधिकतम उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाए।

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत रही है। इस समाज में अपने नियम, कानून और मूल्य रहे हैं, लेकिन समय के साथ यह समाज पीछे रह गया। इसे मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की गई हैं।

महाराष्ट्र में कुल जनसंख्या का ९.५% हिस्सा आदिवासी समाज से आता है, जबकि देश की कुल आदिवासी जनसंख्या का १०% महाराष्ट्र में निवास करता है। इसलिए महाराष्ट्र को आदिवासी बहुल राज्य के रूप में देखा जाता है। आदिवासी बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले और उनकी प्राकृतिक प्रतिभा को सही मंच मिले, इसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है।

सीएसआर फंड के माध्यम से आदिवासी समाज का सशक्तिकरण

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके ने कहा कि आदिवासी विभाग के माध्यम से सीएसआर फॉर चेंज नामक पहल पहली बार शुरू की गई है। इस पहल के तहत सामाजिक दायित्व भागीदारी का उपयोग आदिवासी समुदाय की प्रगति के लिए किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कंपनियों की सामाजिक दायित्व भागीदारी आदिवासी कल्याण योजनाओं को सशक्त बनाएगी और इससे आदिवासी समाज के विकास में तेजी आएगी।

इस अवसर पर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। चर्चा सत्र का संचालन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (णछ्उझ) की कार्यक्रम प्रमुख श्रीतमा गुप्तभया ने किया।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

पुणे और बीड जिलों को मात्र एक महीने में दो नए वेटरनरी कॉलेज, संरक्षक मंत्री अजित पवार की बड़ी सौगात

बारामती और परली वेटरनरी कॉलेजों को राज्य कैबिनेट की मंजूरी

मुंबई:(संवाददाता)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पहल पर पुणे और बीड जिलों में दो नए पशुचिकित्सा (वेटरनरी) कॉलेजों की स्थापना को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जनवरी में बारामती में आयोजित 'कृषि २०२५' प्रदर्शनी के दौरान अजित पवार ने बारामती (पुणे) और परली (बीड) में वेटरनरी कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। मात्र एक महीने के भीतर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गईं और मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।

पशुपालन को मिलेगा बढ़ावा, वेटरनरी सेवाओं में होगा सुधार

महाराष्ट्र एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि के साथ-साथ पशुपालन का विकास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बारामती और परली में नए वेटरनरी कॉलेजों की स्थापना से मवेशी पालकों को आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली पशुचिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, राज्य में प्रशिक्षित वेटरनरी डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, जिससे मवेशियों के स्वास्थ्य और विकास में सुधार होगा। किसानों की मांग पर लिया गया फैसला

जनवरी २०२५ में बारामती में आयोजित 'कृषि २०२५' प्रदर्शनी के दौरान किसानों और पशुपालकों ने बारामती में वेटरनरी कॉलेज की मांग की थी। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए अजित पवार ने इसकी घोषणा की। मात्र एक महीने के अंदर उन्होंने इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट से मंजूरी दिलवा दी।

बारामती के करहावागज में ८२ एकड़ और परली के लोणी में ७५ एकड़ भूमि पर ये सरकारी वेटरनरी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अजित पवार का महाराष्ट्र को १ ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को १ ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि और कृषि आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए यह अहम निर्णय लिया। वर्तमान में राज्य में वेटरनरी सेवाओं और डॉक्टरों की अत्यधिक मांग है। नए कॉलेजों के माध्यम से प्रशिक्षित पशुचिकित्सकों की संख्या में वृद्धि होगी और मवेशियों की देखभाल और सुरक्षा की सेवाएं और मजबूत होंगी। राज्य सरकार से ११२९.१६ करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी सरकारी वेटरनरी कॉलेजों के लिए बड़ी संख्या में नौकरियों को मंजूरी दी गई है। प्रत्येक कॉलेज के लिए ९६ शिक्षक और १३८ गैर-शिक्षण कर्मचारियों के स्थायी पदों को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा, ४२ पदों को अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। बारामती और परली में बनने वाले इन कॉलेजों के लिए कुल ११२९.१६ करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई। प्रत्येक कॉलेज पर ५६४.५८ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस बजट से आधुनिक अनुसंधान केंद्र, उन्नत प्रयोगशालाएं और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसानों और पशुपालकों के लिए राहतभरी खबर इस फैसले से राज्य के पशुपालकों को अत्यधिक लाभ होगा और आधुनिक वेटरनरी सेवाएं और आसानी से उपलब्ध होंगी। विशेष रूप से बारामती और परली के किसानों और पशुपालकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इससे कृषि आधारित व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान और नई तकनीकों के लिए नए अवसर खुलेंगे। अजित पवार की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और पुणे-बीड जिलों के संरक्षक मंत्री के रूप में अजित पवार ने मात्र एक महीने के भीतर इस महत्वपूर्ण निर्णय को अमल में लाकर जनता के हित में बड़ा कदम उठाया है। इससे न केवल पुणे और बीड जिलों का, बल्कि पूरे महाराष्ट्र का विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा।

अवैध शराब के खिलाफ परली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

४ लाख से अधिक का माल जब्त

परली, २५ फरवरी (प्रतिनिधि):

परली में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए ४,१४,३६० रुपये का माल जब्त किया। कार में हो रही थी शराब की तस्करी परली शहर में २५ फरवरी को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति टाटा इंडिका कार से अवैध शराब की तस्करी कर रहा है। इस पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए वाहन का पीछा कर उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने टाटा इंडिका कार (चक्र २३, ६५८०) की तलाशी ली, तो उसमें २१ बॉक्स देशी-विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत १,१४,३६० रुपये आंकी गई। इसके साथ ही ३ लाख रुपये मूल्य की टाटा इंडिका कार भी जब्त कर ली गई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस की अहम भूमिका इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत, अपर पुलिस अधीक्षक चेतना तिडके और पुलिस निरीक्षक रघुनाथ नाचण के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में बालाजी दराडे, भास्कर केंद्र, बापू नागरगोजे, सुरज गुट्टे, गोविंद भताने, रामकिशन रेडेवाड और पंडित पांचाळ की विशेष भूमिका रही।

ज्येष्ठों के मार्गदर्शन में युवा वर्ग सक्रिय, लेकिन बीड नगर परिषद और जिला प्रशासन निष्क्रिय

ऐतिहासिक कारंजा टॉवर की दुर्दशा पर अब भी प्रशासन चुप

बीड (प्रतिनिधि):

शहर के ऐतिहासिक कारंजा टॉवर की दुर्दशा को लेकर पहले निवेदन और फिर खबरों के माध्यम से जागरूकता फैलाने के बाद, ज्येष्ठों के मार्गदर्शन में युवा वर्ग ने सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन बीड नगर परिषद और जिला प्रशासन अभी भी निष्क्रिय बना हुआ है।

निवेदन सौंपे १० दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर प्रशासन इसी तरह निष्क्रिय बना रहा, तो बीड शहर की पहचान माने जाने वाले ऐतिहासिक कारंजा टॉवर का पुनरुद्धार कब और कैसे होगा?

प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल

मुक्त पत्रकार एस.एम. यूसुफ और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रमेशराव गंगाधरे ने इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने बताया कि १४ फरवरी २०२५ को जिलाधिकारी, मुख्याधिकारी, तहसीलदार और पुलिस अधीक्षक को इस मुद्दे पर एक औपचारिक निवेदन सौंपा गया था। इसके बाद, मीडिया में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, जिससे जनता में कारंजा टॉवर के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ी। युवाओं का प्रयास, कारंजा टॉवर के आसपास सुधार कार्य शुरू

युवाओं के स्वयंसेवी प्रयासों से टॉवर के पास चार सीमेंट की बेंच लगाई गई हैं, जिससे अब बुजुर्ग और बच्चे वहां बैठकर आनंद ले सकते हैं।

टॉवर के सामने लगे बड़े-बड़े बैनर और उनकी फ्रेम हटा दी गई हैं।

१० साल पहले बने फव्वारे के जलाशय से गंदगी, कचरा और गाद हटाकर सफाई की गई है।

टॉवर की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए युवाओं ने श्रमदान किया।

अब भी कई कार्य बाकी, प्रशासन की जिम्मेदारी हालांकि, अब भी कई जरूरी कार्य बाकी हैं, जिनमें: टॉवर के पश्चिम और उत्तर भाग में और बेंच लगाना

फव्वारे को फिर से चालू करना

१० साल पहले लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत और पुनः संचालन

बंद पड़ी घड़ियों को चालू करना

टॉवर की दीवारों को नुकसान पहुंचाने वाली पेड़ों की शाखाएं काटना

टॉवर की आंतरिक और बाहरी रंगाई-पुताई करना

नगर परिषद और जिला प्रशासन की निष्क्रियता

जबकि युवा वर्ग अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, बीड नगर परिषद और जिला प्रशासन की निष्क्रियता साफ नजर आ रही है। अगर प्रशासन इसी तरह निष्क्रिय बना रहा तो कारंजा टॉवर की ऐतिहासिक विरासत का पुनरुद्धार कब होगा और किसके भरोसे होगा?

मुक्त पत्रकार एस.एम. यूसुफ और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रमेशराव गंगाधरे ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने और कारंजा टॉवर के सौंदर्यीकरण के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है।

बसपा बीड जिला अध्यक्ष पद पर प्रशांत वासनिक की नियुक्ति

बीड, २३ फरवरी:

राष्ट्रसंत गाडगेबाबा जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की बीड जिला कमेटी के पुनर्गठन के लिए महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव व मराठवाड़ा ज़ोन प्रभारी मुकुंद दादा सोनवणे बीड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आंदोलन की दिशा और गाडगेबाबा के योगदान पर प्रकाश डाला।

गाडगेबाबा का बहुमूल्य योगदान

मुकुंद दादा सोनवणे ने कहा कि महामानवों के आंदोलन में गाडगेबाबा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भी गाडगेबाबा का बहुत सम्मान करते थे। गाडगेबाबा लोगों को उपदेश देते हुए कहते थे □

अगर तुम्हें बड़ा बनना है, तो आंबेडकर जितना बड़ा बनो, और अगर तुम्हें पढ़ना है, तो आंबेडकर जितना पढ़ो!

इसके अलावा, गाडगेबाबा ने पंढरपुर स्थित अपनी धर्मशाला की इमारत भी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को समर्पित की थी।

प्रशांत वासनिक बने बसपा बीड जिला अध्यक्ष

बैठक में बीड जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। बसपा ने आंबेडकरी आंदोलन के अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ता प्रशांत वासनिक को बीड जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी।

इसके अलावा, अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ इस प्रकार हैं:

बीड विधानसभा अध्यक्ष: रजनीकांत वाघमारे

गेवराई विधानसभा अध्यक्ष: कल्याण वाव्हळ

परली विधानसभा अध्यक्ष: प्रमोद मुळे

केज विधानसभा अध्यक्ष: समाधान काळुंके

डॉ. सिद्धार्थ टाकणखार पार्टी से निष्कासित बसपा के पूर्व प्रदेश महासचिव व बीड जिला प्रभारी डॉ. सिद्धार्थ टाकणखार को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को फोन पर गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एड. सुनीलजी डोंगरे के आदेशानुसार पार्टी से स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया गया।

बैठक में कई पदाधिकारी रहे उपस्थित

इस बैठक में मराठवाड़ा ज़ोन प्रभारी डॉ. अनंत गायकवाड, डी.एल. उजगरे, अविनाश शिंगारे, संजय हराळ, आकाश शिंदे, युवराज जाधव, अमोल डोंगरे, वसंत बनसोडे, एस.आर. सय्यद, यदुनाथ वाव्हळ, वैभव शिंदे, सागर वाघमारे, आदित्य शिंदे, संतोष कांबळे सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

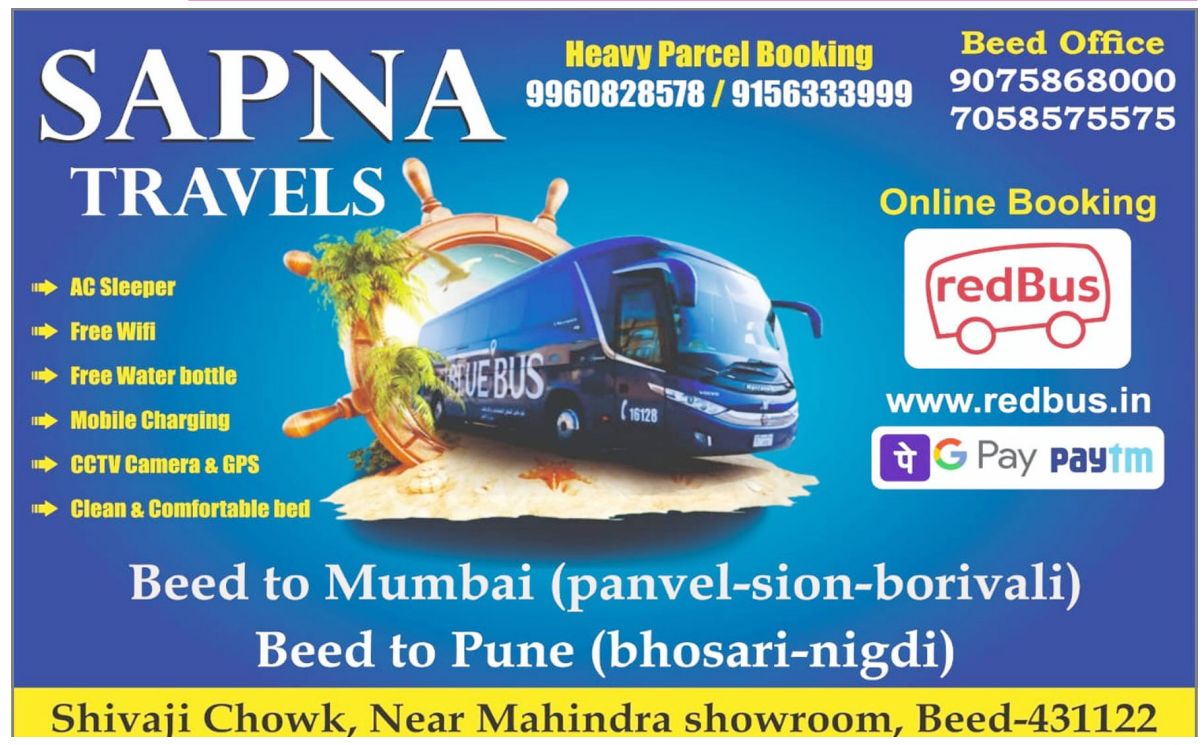

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com